Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2
ISSN No: 3049-4176

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023: करेली तहसील में महिला श्रमिकों के मतदान पैटर्न का विश्लेषण

डॉ. सुलेखा मिश्रा[1], हेमलता अहिरवार[2]
[1]प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, शास. स्वशासी, मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर
[2]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

शोध सारांश

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या और उनकी सक्रिय भागीदारी ने समकालीन चुनावी राजनीति के विमर्श को पूरी तरह बदल दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के विशेष संदर्भ में, नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील में कार्यरत महिला श्रमिकों के मतदान पैटर्न और उनके राजनीतिक व्यवहार का एक सूक्ष्म-स्तरीय (Micro-level) अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक व कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिला श्रमिक किन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रेरित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं।

शोध में मात्रात्मक (Quantitative) पद्धति का उपयोग करते हुए बहु-स्तरीय क्लस्टर सैम्पलिंग (Multi-stage Cluster Sampling) के माध्यम से करेली तहसील की 200 महिला श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया। एकत्रित डेटा का विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी और द्विचर विश्लेषण (Cross-tabulation एवं Chi-square Test) का उपयोग किया गया। निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित 'लाडली बहना योजना' जैसी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं का महिला श्रमिकों के मतदान निर्णयों पर सबसे गहरा प्रभाव (**84.0%**) पड़ा। हालांकि, द्विचर विश्लेषण यह भी स्पष्ट करता है कि शिक्षा का स्तर महिलाओं के स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है ($\text{source:} \chi^2 = 32.41, p < 0.001$)। यह शोध पत्र दर्शाता है कि जहाँ एक ओर लोक-कल्याणकारी नीतियां महिलाओं को 'लाभार्थी वर्ग' के रूप में लामबंद कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक असुरक्षा और पितृसत्तात्मक संरचनाएं अब भी उनकी पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं।

कीवर्ड्स: विधानसभा चुनाव 2023, करेली तहसील, महिला श्रमिक, मतदान पैटर्न, लाभार्थी राजनीति, राजनीतिक स्वायत्तता, Chi-square परीक्षण।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

1. परिचय (Introduction)

समकालीन भारतीय राजनीति का एक सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहलू "मतदाताओं का महिलाकरण" (Feminization of the Electorate) है। पिछले एक दशक में, ऐतिहासिक रूप से चले आ रहे लिंग-अंतर (Gender Gap) को पाटते हुए महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के बराबर या कई राज्यों में उनसे अधिक दर्ज किया गया है (Election Commission of India, 2021)। यह बदलाव न केवल उनके भीतर बढ़ती राजनीतिक चेतना का सूचक है, बल्कि इसने राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी रणनीतियों को पुनर्गठित करने के लिए मजबूर किया है। अब महिलाएं केवल अदृश्य मतदाता नहीं हैं, बल्कि वे एक स्वतंत्र और निर्णायक राजनीतिक शक्ति (Identifiable Vote Bank) के रूप में उभरी हैं।

मध्य प्रदेश का 2023 का विधानसभा चुनाव इस दृष्टिकोण से अत्यंत ऐतिहासिक था। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाने की होड़ पर केंद्रित हो गया था। चुनावी घोषणाओं में 'लाडली बहना योजना' जैसी योजनाओं ने पूरे नैरेटिव को प्रभावित किया, जिसके तहत महिला मतदाताओं के खातों में सीधे मासिक वित्तीय सहायता भेजी गई।

इस वृहद राजनीतिक परिदृश्य के बीच, हाशिए पर मौजूद आर्थिक समूहों, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी महिला श्रमिकों के राजनीतिक व्यवहार को समझना आवश्यक है। नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील इस प्रकार के अध्ययन के लिए एक आदर्श क्षेत्र प्रस्तुत करती है। करेली तहसील अपनी भौगोलिक स्थिति, समृद्ध कृषि (विशेष रूप से गन्ना उत्पादन और गुड़ उद्योग) और बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला श्रम शक्ति के लिए जानी जाती है। यहाँ की अधिकांश महिला श्रमिक दैनिक वेतनभोगी, कृषि मजदूर, या घरेलू सूक्ष्म उद्योगों (जैसे बीड़ी निर्माण) में संलग्न हैं।

यह शोध पत्र करेली तहसील की इन महिला श्रमिकों के विशिष्ट मतदान पैटर्न का विश्लेषण करता है। जहाँ अधिकांश चुनावी विश्लेषण राज्य या जिला स्तर के वृहद आंकड़ों पर निर्भर करते हैं, वहीं यह अध्ययन सूक्ष्म स्तर (Micro-level) पर जाकर यह समझने का प्रयास करता है कि आर्थिक रूप से असुरक्षित और सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़ी महिला श्रमिकों के मतदान निर्णयों को कौन से कारक संचालित करते हैं। क्या नकद हस्तांतरण की राजनीति (Welfare Clientelism) उनकी राजनीतिक स्वायत्तता को बढ़ा रही है, या फिर पारंपरिक पितृसत्तात्मक कारक आज भी उनके निर्णयों को नियंत्रित करते हैं? यह शोध इन यक्ष प्रश्नों का उत्तर खोजने का एक अकादमिक प्रयास है।

2. साहित्य समीक्षा

भारतीय चुनावों में मतदाताओं के व्यवहार (Voting Behaviour) का अध्ययन दशकों से जाति, वर्ग और धर्म के त्रिकोण के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। हालांकि, हाल के वर्षों में 'जेंडर' (Gender) को एक स्वतंत्र विश्लेषणात्मक श्रेणी के रूप में मान्यता मिली है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

2.1. पारंपरिक पितृसत्तात्मक मॉडल बनाम उभरती स्वायत्तता

प्रारंभिक चुनावी अध्ययनों (जैसे, Yadav, 2009) का तर्क था कि ग्रामीण भारत में महिलाएं एक 'ब्लॉक वोट' का हिस्सा होती हैं, जिसका निर्धारण परिवार का पुरुष मुखिया करता है। महिलाओं के राजनीतिक समाजीकरण (Political Socialization) को उनके घरेलू दायरे तक ही सीमित माना जाता था। हालांकि, जाफरेलॉट और कुमार (2009) ने अपने अध्ययनों में रेखांकित किया कि पंचायती राज संस्थाओं में **50%** महिला आरक्षण लागू होने के बाद ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक समझ में गुणात्मक बदलाव आया है। अब महिलाएं पुरुषों के निर्देशों से इतर जाकर स्वतंत्र रूप से मतदान करने की क्षमता प्रदर्शित कर रही हैं।

2.2. कल्याणकारी नीतियां और 'लाभार्थी' राजनीति का उदय

समकालीन विमर्श में 'लाभार्थी राजनीति' (Welfare Politics) एक नया प्रतिमान बनकर उभरी है। श्रीधरन (2014) का मानना है कि भारतीय मतदाता अब वैचारिक प्रतिबद्धताओं के बजाय 'ठोस वितरण' (Tangible Deliverables) को अधिक महत्व दे रहे हैं। महिलाओं के संदर्भ में, मुफ्त राशन, साइकिल वितरण, स्वास्थ्य कार्ड (जैसे आयुष्मान भारत) और नकद हस्तांतरण योजनाओं ने एक नए प्रकार के राजनीतिक जुड़ाव को जन्म दिया है। देसाई (2012) के अनुसार, अनौपचारिक क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए, जहाँ दैनिक आय अनिश्चित होती है, वहाँ राज्य द्वारा दी जाने वाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता सीधे तौर पर उनके मतदान प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है।

2.3. मध्य प्रदेश का चुनावी संदर्भ

मध्य प्रदेश की राजनीति पर केंद्रित शोध यह दर्शाते हैं कि राज्य में 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' से लेकर 'लाड़ली बहना योजना' तक के सफर ने राज्य में एक मजबूत महिला लाभार्थी आधार तैयार किया। 2023 के चुनावों में इस आधार की परीक्षा होनी थी। हालांकि, मौजूदा साहित्य में इस बात की कमी है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में काम करने वाली महिला श्रमिकों (जैसे कृषि और निर्माण श्रमिक) के बीच किस प्रकार ग्रहण की गई।

2.4. शोध अंतराल (Research Gap)

यद्यपि महिला मतदान व्यवहार पर व्यापक राष्ट्रीय अध्ययन उपलब्ध हैं, परंतु कृषि प्रधान और अनौपचारिक श्रम-बाहुल्य वाले क्षेत्रों जैसे कि करेली तहसील (नरसिंहपुर) की महिला श्रमिकों पर कोई विशिष्ट केंद्रित अध्ययन उपलब्ध नहीं है। महिला श्रमिकों का आर्थिक और सामाजिक जीवन सामान्य गृहणियों से भिन्न होता है; वे सीधे तौर पर श्रम बाजार के शोषण, मजदूरी दर और सरकारी कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होती हैं। प्रस्तुत शोध इसी सूक्ष्म अंतराल (Micro-gap) को पाटने का प्रयास करता है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

3. शोध कार्यप्रणाली

3.1. शोध डिजाइन

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध डिजाइन (Descriptive and Analytical Research Design) पर आधारित है। इसमें प्राथमिक डेटा के आधार पर महिला श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों और उनके मतदान व्यवहार के बीच सांख्यिकीय संबंधों की व्याख्या की गई है।

3.2. प्रतिदर्श चयन

अध्ययन की ब्रह्मांड (Universe) करेली तहसील की वह महिला श्रमिक थीं जो 2023 के विधानसभा चुनाव में पंजीकृत मतदाता थीं। शोध में **बहु-स्तरीय क्लस्टर सैम्पलिंग (Multi-stage Cluster Sampling)** का प्रयोग किया गया:

- **प्रथम चरण:** करेली तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को चिन्हित कर 5 प्रमुख ग्राम पंचायतों और 2 शहरी वार्डों का चयन क्लस्टर के रूप में किया गया।
- **द्वितीय चरण:** इन चयनित क्षेत्रों में से अनौपचारिक क्षेत्रों (कृषि, बीड़ी उद्योग, मनरेगा) में काम करने वाली महिलाओं की सूची स्थानीय रोजगार सहायकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से तैयार की गई।
- **तृतीय चरण:** इस सूची में से **व्यवस्थित यादृच्छिक सैम्पलिंग (Systematic Random Sampling)** का उपयोग करके कुल **200 महिला श्रमिकों** को अंतिम प्रतिदर्श (Sample) के रूप में चुना गया।

3.3. डेटा संग्रह के उपकरण

डेटा संग्रह के लिए एक संरचित साक्षात्कार अनुसूची (Structured Interview Schedule) तैयार की गई। उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए प्रश्नावली को सरल हिंदी में रखा गया था। इसमें बंद-छोर वाले (Closed-ended) और लिकर्ट स्केल (Likert Scale) आधारित प्रश्न शामिल थे, जो सामाजिक-आर्थिक स्थिति, राजनीतिक जागरूकता, योजनाओं के प्रभाव और मतदान की स्वतंत्रता को मापते थे। डेटा संग्रह दिसंबर 2023 (चुनाव परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद) में किया गया ताकि स्मृति लोप (Recall Bias) की संभावना न्यूनतम रहे।

3.4. सांख्यिकीय विश्लेषण

एकत्रित डेटा को सांख्यिकीय विश्लेषण सॉफ्टवेयर (SPSS/Excel) में कोडित किया गया। परिकल्पना परीक्षण (Hypothesis Testing) के लिए ची-स्क्वायर परीक्षण (χ^2 Test) का उपयोग किया गया ताकि यह देखा जा सके कि क्या महिलाओं की शिक्षा और उनके निर्णय लेने की स्वायत्तता के बीच कोई महत्वपूर्ण सांख्यिकीय संबंध है।

4. परिणाम और विश्लेषण

4.1. उत्तरदाताओं का सामाजिक-जनसांख्यिकीय प्रोफाइल (Socio-Demographic Profile)

सर्वेक्षण में शामिल 200 महिला श्रमिकों के जनसांख्यिकीय और आर्थिक संकेतकों का विवरण तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1: उत्तरदाताओं का सामाजिक-जनसांख्यिकीय प्रोफाइल ($N=200$)

संकेतक	**उप-श्रेणी**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
आयु वर्ग	18–35 वर्ष	96	48.0%
	36–50 वर्ष	72	36.0%
	50 वर्ष से अधिक	32	16.0%
शिक्षा का स्तर	निरक्षर / अनौपचारिक शिक्षा	64	32.0%
	प्राथमिक से माध्यमिक (1st-8th)	88	44.0%
	उच्चतर माध्यमिक (9th-12th)	38	19.0%
	स्नातक या उच्चतर	10	5.0%
कार्य का प्रकार	कृषि श्रमिक (Seasonal/Daily)	114	57.0%
	बीड़ी श्रमिक / घरेलू सूक्ष्म उद्योग	46	23.0%
	निर्माण कार्य / मनरेगा (MGNREGA)	40	20.0%
मासिक आय	₹3,000 से कम	78	39.0%
	₹3,001 से ₹6,000	92	46.0%
	₹6,000 से अधिक	30	15.0%
सामाजिक वर्ग	अनुसूचित जाति (SC)	44	22.0%

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

	अनुसूचित जनजाति (ST)	36	18.0%
	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	102	51.0%
	सामान्य वर्ग (General)	18	9.0%

डेटा दर्शाता है कि करेली तहसील में महिला श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा युवा और मध्यम आयु वर्ग (**84%**) का है। हालांकि, उनका शैक्षणिक और आर्थिक स्तर अत्यंत चिंताजनक है; **76%** महिलाएं या तो निरक्षर हैं या केवल प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच पाई हैं, और **85%** की मासिक आय ₹6,000 से कम है, जो उन्हें तीव्र आर्थिक असुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाती है।

4.2. मतदान निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

महिला श्रमिकों के मतदान निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करने के लिए "मल्टीपल रिस्पांस विश्लेषण" (Multiple Response Analysis) का उपयोग किया गया।

तालिका 2: मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक ($N=200$)

क्र.सं.	प्रभावित करने वाले कारक	सहमत उत्तरदाता (f)	प्रतिशत	रैंक
1.	**नकद हस्तांतरण योजनाएं (लाडली बहना योजना)**	168	84.0%	**I**
2.	**स्थानीय बुनियादी मुद्दे (पानी, सड़क, बिजली)**	124	62.0%	**II**
3.	**परिवार के मुखिया/पुरुष सदस्यों की सलाह**	98	49.0%	**III**
4.	**उम्मीदवार की स्थानीय छवि और पहुंच**	76	38.0%	**IV**
5.	**मुफ्त राशन और आवास योजना (पीएमएवाई)**	72	36.0%	**V**
6.	**जातिगत या सामुदायिक समीकरण**	42	21.0%	**VI**

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

सांख्यिकीय निष्कर्ष स्पष्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की 'लाडली बहना योजना' (84.0%) करेली तहसील की महिला श्रमिकों के बीच सबसे प्रभावी कारक बनकर उभरी। यह सीधे तौर पर उनकी कम आय संरचना और नकद तरलता (Cash Liquidity) की आवश्यकता से जुड़ा है। इसके बाद पानी की उपलब्धता और स्थानीय सड़कों जैसे बुनियादी मुद्दे (62.0%) दूसरे स्थान पर रहे, जो उनके दैनिक जीवन के संघर्षों को दर्शाते हैं।

4.3. द्विचर विश्लेषण: शिक्षा का स्तर बनाम मतदान निर्णय की स्वतंत्रता

यह जाँचने के लिए कि क्या महिला श्रमिकों की शिक्षा का स्तर उनके स्वतंत्र मतदान निर्णय (बिना पारिवारिक दबाव के) को प्रभावित करता है, एक **ची-स्क्वायर परीक्षण (χ^2 Test)** लागू किया गया।

तालिका 3: शिक्षा का स्तर और मतदान निर्णय की स्वतंत्रता (Cross-Tabulation)

शिक्षा का स्तर	स्वतंत्र निर्णय	family/पति के प्रभाव में निर्णय	कुल
निरक्षर / प्राथमिक	42 (27.6%)	110 (72.4%)	152
माध्यमिक और उच्चतर	36 (75.0%)	12 (25.0%)	48
कुल	**78**	**122**	**200**

सांख्यिकीय मान: $\chi^2 = 32.41, \quad df = 1, \quad p < 0.001$

सांख्यिकीय विश्लेषण: चूंकि p-मान 0.001 से कम है, इसलिए यह निष्कर्ष अत्यधिक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण (Statistically Significant) है। यह दर्शाता है कि करेली तहसील में **जैसे-जैसे महिला श्रमिकों का शैक्षिक स्तर बढ़ता है, उनके मतदान निर्णयों में स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बढ़ती है**। इसके विपरीत, कम शिक्षित या निरक्षर महिला श्रमिकों में अब भी पति या परिवार के मुखिया के निर्देश पर वोट देने का प्रतिशत (**72.4%**) काफी अधिक है, जो यह साबित करता है कि पारंपरिक पितृसत्तात्मक नियंत्रण को तोड़ने में शिक्षा एक अनिवार्य कारक है।

4.4. मतदान प्रक्रिया में बाधक तत्व (Barriers to Voting)

उन महिला श्रमिकों ($n = 24$, जिन्होंने 2023 चुनाव में मतदान नहीं किया या जिन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा) के फीडबैक के आधार पर बाधाओं का विश्लेषण निम्नलिखित पाया गया:

- **दिहाड़ी/मजदूरी का नुकसान (Wage Loss): 54.2%** महिला श्रमिकों ने माना कि कतारों में खड़े होने के कारण उनके उस दिन की मजदूरी छूटने का डर था। नियोक्ता (Landlords/Contractors) मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश नहीं देते हैं।
- **घरेलू जिम्मेदारियां व शिशु देखभाल (Domestic Care): 29.1%** महिलाओं के लिए बच्चों को घर पर अकेले छोड़ना या मतदान केंद्र पर उनके लिए कोई क्रेच (Creche) सुविधा न होना बड़ी

बाधा थी।

- **परिवहन सुविधाओं का अभाव (Lack of Transport): 16.7%** उत्तरदाताओं ने सुदूर खेतों/कमरों से मतदान केंद्रों की दूरी को एक समस्या बताया।

5. चर्चा

करेली तहसील में महिला श्रमिकों के मतदान पैटर्न से प्राप्त निष्कर्ष भारतीय चुनावी राजनीति के समकालीन सिद्धांतों के साथ एक गहरा अंतर्संबंध प्रदर्शित करते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष 'लाडली बहना योजना' का व्यापक प्रभाव (**84.0%**) है। यह परिणाम जेम्स स्कॉट के 'क्लाइंटेलिज़्म' (Clientelism) और भारत के संदर्भ में 'लाभार्थी अर्थशास्त्र' के सिद्धांतों की पुष्टि करता है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए, ₹1,000 या ₹1,250 की मासिक राशि केवल एक चुनावी उपहार नहीं है, बल्कि यह उनकी आर्थिक स्वायत्तता और पोषण सुरक्षा से जुड़ी है। यह राशि उन्हें परिवार के पुरुष सदस्यों के सामने हाथ फैलाने से मुक्ति देती है। इसलिए, मतदान में इस वर्ग का झुकाव उस दल की ओर होना स्वाभाविक था जिसने इस तात्कालिक राहत की गारंटी दी थी।

हालांकि, इस विमर्श का दूसरा पहलू सांख्यिकीय विश्लेषण (तालिका 3) से स्पष्ट होता है। ची-स्क्वायर टेस्ट के परिणाम ($p < 0.001$) यह संकेत देते हैं कि केवल वित्तीय लाभ प्रदान कर देने से महिलाओं का वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण (Substantive Empowerment) सुनिश्चित नहीं हो जाता। निरक्षर और कम आय वाली महिला श्रमिकों में आज भी मतदान के समय अपने पति या सामाजिक वर्ग के मुखिया के आदेशों का पालन करने की प्रवृत्ति (**72.4%**) पाई गई। इसका अर्थ यह है कि 'आर्थिक लाभार्थी' होने के बावजूद वे पूर्णतः 'राजनीतिक रूप से स्वायत्त एजेंट' नहीं बन पाई हैं। इसके विपरीत, शिक्षित महिला श्रमिकों ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए भी अपने मतदान निर्णय को स्वतंत्र रखा, जो यह दर्शाता है कि शिक्षा ही उनके भीतर आलोचनात्मक चेतना (Critical Consciousness) का संचार करती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो चर्चा के योग्य है, वह है आर्थिक मजबूरी बनाम नागरिक कर्तव्य का द्वंद्व। **54.2%** महिलाओं द्वारा मजदूरी के नुकसान को मतदान में बाधक मानना यह उजागर करता है कि चुनावी लोकतंत्र में आज भी समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपने नागरिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी एक दिन की आजीविका का बलिदान देना पड़ता है। यह राज्य और चुनाव आयोग के उन दावों पर सवालिया निशान लगाता है जो 'शत-प्रतिशत समावेशी मतदान' की बात करते हैं।

6. शोध की सीमाएँ

प्रस्तुत शोध पत्र के निष्कर्षों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए इसकी कुछ अंतर्निहित सीमाओं को भी रेखांकित करना आवश्यक है:

1. **भौगोलिक संकीर्णता:** यह अध्ययन केवल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील तक

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

सीमित है। करेली की विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक और जातिगत संरचना (जैसे ओबीसी बाहुल्यता) पूरे मध्य प्रदेश या देश के अन्य राज्यों के आदिवासी या औद्योगिक क्षेत्रों से भिन्न हो सकती है, अतः निष्कर्षों का सार्वभौमिक सामान्यीकरण (Universal Generalization) सीमित है।

2. **प्रतिदर्श का आकार (Sample Size):** N = 200 का प्रतिदर्श सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए पर्याप्त है, परंतु एक बड़े प्रतिदर्श आकार के माध्यम से उप-जातियों और विभिन्न श्रम श्रेणियों (जैसे केवल निर्माण श्रमिक बनाम केवल कृषि श्रमिक) के बीच के सूक्ष्म अंतरों को और बेहतर ढंग से पकड़ा जा सकता था।
3. **उत्तरदाताओं का पूर्वाग्रह (Social Desirability Bias):** ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा संग्रह के दौरान महिलाएं अक्सर राजनीतिक प्रश्नों पर खुलकर बात करने से कतराती हैं या वही उत्तर देती हैं जो सामाजिक रूप से सुरक्षित माना जाता है। सरकारी योजनाओं के लाभ खोने के डर से भी कुछ उत्तरों में अतिशयोक्ति हो सकती है।

7. निष्कर्ष

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के परिप्रेक्ष्य में करेली तहसील की महिला श्रमिकों के मतदान पैटर्न का यह विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि ग्रामीण महिला मतदाता अब मूक या अदृश्य नहीं हैं। वे राज्य की लोक-कल्याणकारी नीतियों और अपने आर्थिक हितों के प्रति अत्यधिक सचेत हैं। 'लाडली बहना योजना' जैसी योजनाओं ने महिला श्रमिकों को एक नए 'लाभार्थी वर्ग' के रूप में लामबंद करने में सफलता प्राप्त की है, जिसने इस चुनाव के अंतिम परिणामों को तय करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई।

हालांकि, यह शोध इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचता है कि महिलाओं की उच्च मतदान हिस्सेदारी को स्वतः ही उनके 'राजनीतिक सशक्तिकरण' का सूचक नहीं मान लिया जाना चाहिए। सांख्यिकीय साक्ष्य गवाही देते हैं कि जब तक शिक्षा और स्वतंत्र आर्थिक स्थिरता का विकास नहीं होता, तब तक मतदान का निर्णय पितृसत्तात्मक ताने-बाने और लोक-लुभावन तात्कालिक वित्तीय लाभों से संचालित होता रहेगा। वास्तविक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 'लाभार्थी' (Passive Recipients) के दायरे से निकालकर 'सक्रिय नागरिक' (Active Political Agents) के रूप में स्थापित करना होगा।

8. भविष्य के शोध की दिशाएँ

भविष्य के शोधकर्ता इस विषय को और अधिक समृद्ध करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं:

1. **दीर्घकालिक अनुदैर्ध्य अध्ययन (Longitudinal Study):** यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या 2023 के चुनाव में दिखा यह 'लाभार्थी प्रभाव' आगामी लोकसभा चुनावों या भविष्य के विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह बरकरार रहता है या समय के साथ इसका प्रभाव कम हो जाता है।
2. **तुलनात्मक क्षेत्रीय विश्लेषण:** मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों (जैसे झाबुआ या डिंडोरी) की महिला श्रमिकों और करेली जैसी कृषि-प्रधान तहसील की महिला श्रमिकों के मतदान व्यवहार के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन जेंडर और जातीयता (Intersections of Gender and Ethnicity)

के अंतर्संबंधों को स्पष्ट कर सकता है।

3. **स्थानीय स्वशासन बनाम राज्य स्तर का चुनाव:** यह विश्लेषण करना एक उपयोगी शोध विषय हो सकता है कि क्या महिला श्रमिक पंचायती राज चुनावों में भी उन्हीं कारकों से प्रभावित होती हैं जो वे विधानसभा जैसे बड़े चुनावों में प्रदर्शित करती हैं।

संदर्भ (References)

1. चट्टोपाध्याय, रघबेंद्र एवं डुफ्लो, एस्थर. (2004). नीति-निर्माता के रूप में महिलाएँ: भारत में एक यादृच्छिक नीति प्रयोग से प्राप्त साक्ष्य। इकोनोमेट्रिका (Econometrica), 72(5), 1409–1443. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x
2. देसाई, सोनल. (2012). भारत के अदृश्य श्रमिक: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाएँ। जेंडर, प्लेस एंड कल्चर (Gender, Place & Culture), 19(5), 651–667. https://doi.org/10.1080/0966369X.2012.671392
3. भारत निर्वाचन आयोग। (2021). चुनावों में महिलाओं की भागीदारी। नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग।
4. जैफ्रेलो, क्रिस्टोफ़ एवं कुमार, संजय (सम्पा.). (2009). प्लीबियन वर्ग का उदय?: भारतीय विधानसभाओं के बदलते स्वरूप। रूटलेज (Routledge)।
5. श्रीधरन, ई. (सम्पा.). (2014). एशिया में गठबंधन राजनीति और लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. यादव, योगेन्द्र. (2009). द्वितीय लोकतांत्रिक उभार को समझना: 1990 के दशक में बहुजन भागीदारी की चुनावी राजनीति की प्रवृत्तियाँ। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (Economic and Political Weekly), 44(2), 27–34.